



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 13 अगस्त, 2003/22 श्रावण, 1925

---

हिमाचल प्रदेश सरकार  
विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 13 अगस्त, 2003

संख्या: एल० एल० आर० डी० (6)-17/2002-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11-08-2003 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी 1903-राजपत्र/2003-13-8-2003—1,455. (1287) मूल्य : एक रुपया।

(वेतन और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक--10) को वर्ष 2003 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

हस्ता०/—

सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

2003 का अधिनियम संख्यांक 13

**हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003**  
(मा० राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 11 अगस्त, 2003 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों का विनियमन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।
- (3) यह प्रथम जुलाई, 1996 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) “न्यायिक अधिकारियों” से राज्य सरकार द्वारा राज्य में हिमाचल प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा और हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
  - (ख) “अधिसूचना” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
  - (ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (घ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
  - (ङ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और
  - (च) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

वेतन ।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और 235 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अधीन न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को विनियमित करने वाले किन्हीं भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान, राज्य में न्यायिक अधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त पश्चात् संदत्त किए जाएंगे ।

नियम बनाने  
की शक्ति ।

4. (1) धारा 3 के उपबन्धों के अध्याधीन राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

व्यावृत्ति ।

5. धारा 3 के उपबन्धों के अध्याधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व न्यायिक अधिकारियों को लागू नियम, न्यायिक अधिकारियों के वेतन तथा सेवा की शर्तों को तब तक विनियमित करते रहेंगे जब तक कि इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन नियम बना नहीं दिए जाते ।

**अनुसूची**  
**(धारा 3 देखें)**

**न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमान :**

**1. सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) :**

- (क) प्रारम्भिक वेतनमान :  
9000-250-10750-300-13150-350-14550 रुपये।
- (ख) 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान:  
10750-300-13150-350-14900 रुपये।
- (ग) प्रथम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात्  
द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :  
12850-300-13150-350-15950-400-17550 रुपये।

**2. सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) :**

- (क) प्रारम्भिक वेतनमान :  
12850-300-13150-350-15950-400-17550 रुपये।
- (ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में 5 वर्ष की सेवा के  
पश्चात् प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :  
14200-350-15950-400-18350 रुपये।
- (ग) प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान में 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण  
होने पर द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान :  
16750-400-19150-450-20500 रुपये।

**3. जिला न्यायाधीश संवर्ग :**

- (क) प्रारम्भिक वेतनमान :  
16750-400-19150-450-20500 रुपये।
- (ख) चयन ग्रेड (काडर के 25 प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) :  
18750-400-19150-450-21850-500-22850 रुपये।
- (ग) सुपर टाईम वेतनमान : (काडर के 10 प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध):  
22850-500-24850 रुपये।

# THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 11TH AUGUST, 2003)

AN

ACT

*to provide for the regulation of the pay and conditions of service of the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title,  
extent and  
commence-  
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on the First day of July, 1996.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "*Judicial Officers*" means the persons appointed by the State Government to the Himachal Pradesh Higher Judicial Service and the Himachal Pradesh Judicial Service in the State ;

(b) "*notification*" means a notification published in the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

(c) "*prescribed*" means prescribed by the rules made under this Act ;

(d) "*SCHEDULE*" means Schedule appended to this Act;

(e) "*State*" means State of Himachal Pradesh ; and

(f) "*State Government*" means the Government of Himachal Pradesh.

**3. Notwithstanding anything contained in any rules regulating the scale of pay to the Judicial Officers made under article 309 read with articles 234 and 235 of the Constitution of India, there shall be paid, immediately after coming into force of this Act, to the Judicial Officers in the State, the pay scales as specified in SCHEDULE.** Salaries.

**4. (1)** Subject to the provisions of section 3, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules regulating the pay and conditions of service of the Judicial Officers. Power to make rules.

**(2)** Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

**5.** Subject to the provisions of section 3, the rules applicable to the Judicial Officers, immediately before the commencement of this Act shall continue to regulate the pay and conditions of service of the Judicial Officers until the rules in that behalf are made under this Act. Saving.

**SCHEDULE**

(See section 3)

The Pay Scales for different cadres of the Judicial Officers :

**1. Civil Judge (Junior Division) :****(a) Initial Scale :** Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-14550.**(b) First stage Assured Career Progression Scale after five years of service :**

Rs. 10750-300-13150-350-14900.

**(c) Second stage Assured Career Progression Scale after five years of service in the First Assured Career Progression Scale :**

Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.

**2. Civil Judge (Senior Division) :****(a) Initial Scale :** Rs. 12850-300-13150-350-15950-400-17550.**(b) First stage Assured Career Progression Scale, after five years of service as Civil Judge (Senior Division) :**  
Rs. 14200-350-15950-400-18350.**(c) Second stage Assured Career Progression Scale on completion of five years of service in the First stage Assured Career Progression Scale :**  
Rs. 16750-400-19150-450-20500.**3. District Judges Cadre :****(a) Initial Scale :** Rs. 16750-400-19150-450-20500.**(b) Selection Grade :** (Available to 25% Officers of the Cadre) :  
Rs. 18750-400-19150-450-21850-500-22850.**(c) Super Time Scale :** (Available to 10% Officers of the Cadre) :  
Rs. 22850-500-24850.